मिल रहा है, केवल पर्चियां मिल रही हैं।...(व्यवधान)... मंत्री जी के आश्वासन देने के बाद आज भी किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति: प्रश्न इतना सा था कि बकाया कितना है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, मोती लाल वोरा जी जो कह रहे हैं, इसके पहले हम दस बार सूबों की सरकार से, एक सरकार से नहीं सब सूबों की सरकारों से इंटरएक्शन करते हैं। उनको कहते भी हैं, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि जो हमारे हाथ में है वह हम करते हैं, हम उनको सलाह-मशविरा दे सकते हैं, उनको परस्यू कर सकते हैं।

Cheap Nepalese vanaspati

*148. SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether he has convened an emergency meeting alongwith the Ministries of Finance, Commerce and Health to look into the onslaught of cheap Nepalese vanaspati putting survival of the Rs. 5,000 crore domestic industry into question;

(b) if so, what was the main agenda of meeting;

(c) whether all the vanaspati units in Eastern India have been closed down following Nepalese dumping triggered by Government's policy;

(d) what decision has been taken to meet the situation; and

(e) to what extent this decision has helped in improving the vanaspati units in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI V. SREENIVASA PRASAD): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) A meeting was convened in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rumandla Raamachandrayya.

Distribution) in January, 2003 to review the issues relating to the Indian vanaspati industry in respect of import of vanaspati under Tariff Rate Quota (TRQ) from Nepal by the canalizing agency, *viz.* the Central Warehousing Corporation (CWC), a Government of India Undertaking. In this context, various problems raised by the industry representatives were discussed. It was, *inter alia,* agreed that the CWC would look into the question of uniform distribution of vanaspati to the States concerned in India and would strive to ensure that the imports of Nepalese vanaspati are made directly by the CWC and, subsequently, distributed by the Corporation equitably among the States, keeping in view the consumption pattern of the respective States. It is, as yet, early to assess the impact of the conclusions reached.

2. There are, at present, 28 vanaspati units in Eastern India, of which 15 units are closed. The reasons underlying the closure of vanaspati units include the creation of production capacity in excess of the availability of raw materials, obsolete technology, poor economics of scale, shift in consumer preference towards soft oils and competition with cheaper imports from Nepal under the Indo-Nepal Treaty of Trade, 2002.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति महोदय, नेपाल से सस्ती वनस्पति आने से आज भारत में हजारों रुपयों के घरेलू उद्योगों के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिह्न लगा है, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: Sir, as I have very clearly said in my statement, one of the reasons is the competition from cheaper import from Nepal under the Indo-Nepal Treaty of Trade, 2002. Apart from this, there are so many reasons underlying the closure of vanaspati units, including the creation of production capacity in excess of the availability of raw materials, obsolete technology, poor economies of scale and shift in consumer preference towards soft oils. These are the main reasons. As per the Indo-Nepal Treaty, we are importing about one lakh metric tons. Sir, our domestic production is very low. There is a demand. So, when the production is low, we have to go for import. According to Indo-Nepal Treaty, we are importing one lakh metric tons. Actually that is not the only reason for the suffering of the domestic industry. As I have said, there are many other reasons. If the import from Nepal has really an impact, why from 1995-96 till 2002-03, the total number of units have increased? In 1995-96, it was 169 units, whereas in

2002-03, it is 235 units. These are all-India figures. In Eastern region also, during 1995-96, total number of units installed was 17, whereas during 2002-03, it is 28. Therefore ...*(Interruptions)*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: How many units are closed?

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: We have closed some. All-India figures, I will give you.

SHRI LALU PRASAD: In which State? ...*(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: In spite of an increase in the number of units, a lot of raw material is being imported, which is forcing the local industry to go.

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: No, no ...*(Interruptions)*

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सर, मंत्री जी कारण बता रहे हैं, परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे।

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: All-India figure during 1995-96 was 63 and in Eastern States it was 9. During 2002-03, number of closed units are 86. It is all-India figure. In Eastern States, it is 50. It is almost same. Now, 45 per cent of the units have been closed.

SHRI LALU PRASAD: In Bihar?

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: I don't have figures about the number of closed units in Bihar.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: इन सब चीजों को दूर करने के लिए आपके पास क्या प्रणाली है? आप वह बताएं, लेकिन आप कारण बता रहे हैं।

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: If it is affected by the import ...*(Interruptions)*

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति महोदय, सेकेण्ड सप्लीमैंटरी। मंत्री जी के जवाब में है कि पूर्वी भारत में फिलहाल 28 यूनिटों में 15 यूनिट बंद हैं, तो इन बंद यूनिटों को खोलने के लिए भारत सरकार क्या विचार रखती है? मंत्री जी कारण मत बताइए, विषय बताइए।

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: Sir, all the units have not been closed. Only 15, out of 28 units, have been closed.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: This is 'only'. सर, हंसने की बात है मंत्री जी के उत्तर में ...(व्यवधान)

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: Sir, the main reason is the unscrupulous practice followed by the manufacturers.They close the existing units, shut the existing units, and shift to Nepal to get the benefit of duty.

श्री प्रेम गुप्ता: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जबकि नेबरिंग स्टेट्स की सब इंडस्ट्री बंद हो गई हैं। मान्यवर, नेपाली आयल जो आता है, उसको फ्रीज़ करके उसके ऊपर सिर्फ लेबल लगाया जाता है, उसकी कोई प्रोसैसिंग नहीं की जाती। इससे इम्पोर्ट ड्यूटी का नुकसान होता, सेल्स टैक्स का नुकसान होता है और इसके कारण टैक्स रिकवरी ज़ीरो हो गई है। वहां बार्डर स्टेट्स की पूरी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, ईस्टर्न यू॰पी॰ की इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो गई हैं। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कैसे बोलते हैं कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं? मान्यवर, सी॰डब्ल्यू॰सी॰ भी इम्पोर्ट करती है जो कि श्री शरद यादव जी की मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सी॰डब्ल्यू॰सी॰ को अलाऊ नहीं करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस बारे में आप क्या कर रहे हैं?

SHRI V. SREENIVASA PRASAD: Sir, he is talking about the duty difference. In Nepal, the duty is 15 per cent, whereas in India it is 65 per cent. As I said earlier, the manufacturers will shut down the existing units here and shift to Nepal in order to get the benefit.

श्री सभापति: यही तो क्वेश्चन है इनका।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य की बात सही है और वाजिब भी है। यह ट्रीटी दो देशों के बीच में है और एक लाख मीट्रिक टन हमको उनसे इम्पोर्ट करना है। इसमें बराबर अंतर आता गया है– पहले 80 परसैंट था, फिर 50 परसैंट हुआ, फिर बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी यहां ड्यूटी 65 प्रतिशत है, वहां 15 प्रतिशत है, लेकिन यह दो देशों की बात है। मैं मानता हूं कि जहां ओपन बार्डर है वहां अगर आदमी एक टिन ले आएगा तो उसे 100-200 रुपये बच जाएंगे।

श्री प्रेम गुप्ता: सर, उस ट्रीटी को ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: आप मेरी बात को तो सुनिए, मैं आपकी ही बात का उत्तर दे रहा हूं। सभापति जी, यह मामला दो कंट्रीज का है और हमारी सरकार ने यह कोशिश की है कि सी॰डब्ल्यू॰सी॰ के ज़रिए हम इसको करें। हम इसको रोकने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। जैसे बार्डर पर कस्टम के लोगों से भी हमने कहा है कि इसके ऊपर चैक होने की जरूरत है।

श्री लालू प्रसाद: पूरे बिहार में वह बिक रहा है।

श्री शरद यादव: मैं आपसे कह रहा हूं कि ओपन बार्डर के कारण वहां एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें बिक रही हैं।

श्री लालू प्रसाद: यहां ''डालडा'' की बात हो रही है।

श्री शरद यादव: ''डालडा'' भी बिक रहा है और बाकी चीज़ें भी बिक रही हैं। सभापति जी, मैं इतना कह सकता हूं कि इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो हमसे संभव हो सकेगा उसे हम करेंगे।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, पाम ऑयल जो इम्पोर्ट हो रहा है नेपाल से, उसकी प्रोसैसिंग होनी चाहिए।

श्री सभापति: इस प्राब्लम को आप यह समझ लीजिए कि दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट के बेसिस पर यह सारा हो रहा है।

श्री प्रेम गुप्ता: सर, उस ट्रीटी के अंदर कुछ प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। सर, उसको इम्पोर्ट करके, फ्रीज़ करके फिर ''डालडा'' के रूप में, ''वनस्पति'' के रूप में इंडिया में डम्प कर दिया जाता है। इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, वहां प्रोसैस करना या नहीं करना हमारे हाथ में नहीं है।

श्री प्रेम गुप्ता: आपको देखना पड़ेगा।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो यहां प्लांट लगाते हैं उनको दस साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट सहूलियतें देती है। इस मामले में जिन लोगों के कारखाने इस तरफ लगे हैं, उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने नेपाल में भी लगा लिए होंगे, लेकिन हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है।

डा० कर्ण सिंह: सभापति जी, मैं अपने ससुराल का पक्षपात नहीं कर रहा हूं...

श्री सभापति: करें तो भी कोई आपत्ति नहीं है।

डा० कर्ण सिंह: लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल भी हमारा मित्र देश है, नेपाल के लोग भी गरीब हैं और अगर नेपाल में कोई आर्थिक प्रगति होती है या वहां के लोगों की कुछ तरक्की होती है तो हम उसका विरोध क्यों करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कुछ ऐसी प्रक्रिया करेंगे जिससे कि भारतवर्ष को भी लाभ हो और नेपाल को भी लाभ हो?

श्री सभापति: वह तो एग्रीमेंट में है। प्रश्न संख्या 149 ।

श्री प्रेम गुप्ता: सर, यह जो एग्रीमेंट किया गया, श्री आई० के० गुजराल के टाइम में किया गया। ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: सर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य बिहार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है।

श्री सभापति: वह तो होगा, आप बार्डर पर हैं न।

श्री लालू प्रसाद: माननीय डा० कर्ण सिंह जी के ससुराल का नुकसान हम लोग क्यों उठाएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण बिहार को टैक्स का नुकसान हो रहा है और वहां की इंडस्ट्री सिक हो रही हैं। नेपाल को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेपाल की जनता और सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं है। यह तो खाली लेबलिंग का मामला है। इसलिए हमारा जो टैक्स का गैप है, जो टैक्स की कमी हो रही है, हमारा कहना है कि टैक्स का वह कम्पनसैशन आप बिहार सरकार को दीजिए। इसका क्या इंतजाम करेंगे? आप मधेपुरा से आते हैं लेकिन जब बिहार की बात होती है तो आप कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हैं। यह जो गैप हो रहा है, आपकी Treaty की वजह से बिहार को जो नुकसान हो रहा है, उसको पूरा करने का इरादा है या नहीं?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, यह सवाल दो देशों के बीच का है। मैं माननीय कर्ण सिंह जी की बात से सहमत हूं कि हमारा एक ही मित्र देश है। ये कह रहे हैं कि हम बिहार से आते हैं तो हम इनकी दया पर नहीं आते हैं। बिहार हमारा भी है और इनका भी है। उसके लिए हमें भी उतनी ही चिंता है, जितनी इनको है। जो कस्टम विभाग है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको मैंने इस बारे में लिखा है। मैं इस बात को pursue कर रहा हूं कि आपके यहां जो दिक्कत है, वह दूर हो और राजस्व में आपको कम से कम घाटा हो।

श्री लालू प्रसाद: कंपनसेशन क्या दे रहे हैं?

श्री शरद यादव: कंपनसेशन तो हमारे हाथ में नहीं है।

High security registration plates

*149. SHRI AMAR SINGH:
SHRI ABU ASIM AZMI:#

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after February 28, 2003 purchasers of

#The question was actually asked on the floor of the House by Shri Abu Asim Azmi